RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 39 | प्रति सोमवार, 3 फरवरी 2025 | मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के कारण फेल हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन

लगभग 50 दिनों तक प्रदेश में नए उद्योगों को नही मिली अनुमति, उद्योग जगत भाजपा से नाराज

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने तब विपक्ष को उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र यानी "गुजरात मॉडल" से परास्त किया था। इस मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता थी जिसमें सरकार द्वारा उद्योगों को आसानी से उद्योग लगाने और व्यापार का स्वस्थ माहौल प्रदान करना था। आज मोदी सरकार औद्योगिक क्रांति की राह पर चल रही है। स्वयं प्रधानमंत्री ने एक नारा

दिया था "minimum government maximum governance"। पर इन सब से इतर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नरेंद्र मोदी के विजन पर गहरा आघात पहुंचा रहे हैं। एक तो मोहन यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, वहीं मुख्यमंत्री पद पर अकर्मण्यता के उदाहरण अब सामने आ रहे हैं। मोहन यादव की एक गलती के कारण प्रदेश में लगभग 50 दिनों तक किसी भी उद्योग को "concent to operate (CTO), concent to establish (CTE)" की अनुमति नहीं मिली थी।

दरअसल मोहन सरकार द्वारा 11 नवंबर को कई आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण आदेश क्रमांक ई-1/240/2024/5/एक के मार्फत निकाला, जिसमें पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन बामरा का ट्रांसफर भी था, उनके स्थान पर डॉ. नवनीत कोठारी को सचिव पर्यावरण के पद पर आसीन कराया गया। यहां यह समझना जरूरी है कि इस आदेश के साथ कोठारी का अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के लिए आदेश नहीं निकाला गया था। पूर्व में गुलशन बामरा, जो कि विभाग के प्रमुख सचिव थे वो पदेन अध्यक्ष भी थे, क्योंकि अध्यक्ष पद खाली रहने पर विभाग का प्रमुख सचिव स्वतः ही अध्यक्ष बन जाते हैं।

(शेष पेज 2 पर)

छत्तीसगढ़ को सुशासित, विकसित और खुशहाल बनाने के संकल्प के साथ प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहे मुख्यमंत्री साय

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनप्रिय और लोकप्रिय नेता है। उन्होंने अपने संवेदशील कार्यप्रणाली का परिचय देते हुए राज्य की जनता के हितो के लिए पिछले दिनो कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मुख्यमंत्री के इन फैसलो का परिणाम यह हुआ कि राज्य के अंदर हर तरफ खुशहाली और उन्नति के भाव दिख रहे है। साय सरकार ने किसानो, महिलाओ, बच्चो और युवाओ के लिए हित मे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए है। छत्तीसगढ़ की सियासत मे किसान एक बड़ा मुद्दा है। सरकार ने धान किसानो से किया वादा पूरा किया। राज्य मे 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपये प्रति एकड़ मे धान की खरीदी हो रही है। इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश के दो सालो के बकाया बोनस का भी भुगतान किया है। छत्तीसगढ़ की सियासत मे गेमचेंजर योजना कही जानी वाली महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत सरकार हर महीने महिलाओं के खाते में एक हजार रुपये ट्रांसफर करती है। सरकार इस योजना की 10 किस्ते जारी कर चुकी है।

नक्सल विरोधी अभियान चल रहा

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक गंभीर समस्या है। राज्य के कई इलाके नक्सलवाद से प्रभावित हैं। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई तेज हुई है। एक साल में एनकाउंटर में 217 नक्सलियों को ढेर किया गया है। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है।

सीबीआई ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान कई घोटाले सामने आए थे। राज्य में बीजेपी की सरकार आने के बाद घोटालों की जांच की जा रही है। शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है। कोयला परिवहन घोटाले की भी जांच हो रही है। सीसीपीएससी की जांच को सरकार ने सीबीआई को सौंपा है। सीबीआई ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। (शेष पेज 8 पर)

क्या भूपेश बघेल के लाडले अशोक जुनेजा को भाजपा देगी सेवा विस्तार?

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ सरकार सेवा और सुशासन का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार प्रदेश के हर एक मामले में जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रही है। यहां तक प्रशासनिक स्तर पर भी जो नियुक्तियां की जा रही हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी जा रही है जिनका सर्विस रिकार्ड बेहतर है। हाल ही में प्रदेश में नया डीजीपी बनना है। इस महत्वपूर्ण पद के लिए कई नामों की चर्चा की जा रही है। उनमें एक नाम अशोक जुनेजा का भी है। अशोक जुनेजा पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खास रहे थे। यहां तक महादेव सट्टा, शराब, कोयला समेत अन्य घोटालों के चरम के दौरान जुनेजा डीजीपी पद पर काबिज थे। सौम्या चौरसिया को तब जेल में वीआईपी सुविधा दी गई थी। यहां तक सूत्रों का दावा है कि फाइलें तब जेल आया करती थी, शायद यही कारण है कि भूपेश बघेल के घोटालों के बाद भी उन पर, उनके खास लोगों पर और उनकी चौकड़ी में शामिल पुलिस अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। (शेष पेज 8 पर)

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के कारण फेल हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन

प्रदेश में आये सैकड़ों निवेशकों को नही मिली जरूरी अनुमतियां और जमीनें

(पेज 1 से जारी)

जबकि यहां पर नवनीत कोठारी सचिव स्तर के अधिकारी थे। मध्य प्रदेश में इस भयंकर प्रशानिक गलती के कारण पूरे 50 दिनों तक किसी भी पुराने एवं नए उद्योगों को "concent to operate (CTO), concent to establish (CTE) की अनुमति नहीं मिल पायी थी। इस दौरान प्रदूषण मंडल में हजारों उद्योगों की अनुमति जस-की-तस पडी रही। गौर करने वाली बात यह है इनमें से कुछ उद्योग वह हैं, जो कि मोहन सरकार के क्षेत्रीय इंडस्ट्रीयल समिट (जो वो पिछले 10 महीने से कर रहे हैं) वो भी थे। मोहन यादव की एक इस गलती के कारण उद्योग जगत को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। साथ ही मध्यप्रदेश की सरकार के ऊपर से इंडस्ट्री लाबी का विश्वास उठ गया है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लगा है। क्योंकि उद्योगों को उन पर विश्वास है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो कि वन एव पर्यावरण मंत्री भी हैं उनका सचिवालय भी इस बात से अनभिज्ञ रहा। यह सिलसिला तब खत्म हुआ जब दिनाँक 30-12-24 को डॉ. नवनीत कोठारी आदेश क्रमांक क्रमांक ई-1/175/2024/5/एक के मार्फत से पदोन्नत होकर विभाग के प्रमुख सचिव बने और स्वतः मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के पदेन अध्यक्ष बने और प्रदेश में 50 दिनों बाद वापस अनुमति प्रदान होना चालू हुआ। अंदरखाने से प्रमुख उद्योगपतियों ने मोहन यादव के ऊपर से अपना विश्वास खोने की बात की है। अब इस सवाल का जवाब क्या आने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में खुद प्रधानमंत्री जवाब देंगे। क्योंकि वो खुद

समिट का उद्घाटन करने आ रहे हैं। इस पूरे मामले में मोहन यादव का इंडस्ट्रियल एक्युमेन सामने आ गया कि यह पूरे समिट सिर्फ नाटक भर या मीडिया इमेज बनाने का प्रयास भर है। क्योंकि जब गवर्नेंस ही उद्योगों के ख़िलाफ़ हो तो इनवेस्टमेंट जमीन पर कैसे आएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश में निवेश लाने को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री पद संभालते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरू किया और अब तक सात संभागों में इसका आयोजन किया जा चुका है। खास बात यह है कि इन सातों कॉन्क्लेव के माध्यम से मोहन यादव की सरकार ने लगभग 02 लाख करोड़ रुपये के निवेश आने का दावा किया है। यही नहीं दो लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने की बात भी इन निवेश के माध्यम से की गई है। लेकिन फिलहाल हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। इसी महीने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। 24 और 25 फरवरी को होने वाली इस समिट के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार विदेशी निवेशकों को प्रदेश में निवेश लाने के लिये प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन मध्यप्रदेश सरकार के आंकड़े कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल पिछले 20 सालों के दौरान भाजपा सरकार ने जो भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की हैं उनमें जो भी निवेशक आये अधिकतर निवेशकों ने यहां निवेश करने से हाथ पीछे खींच लिये। उसका सबसे बड़ा कारण था यहां सिंगल विंडो सिस्टम न होना। प्रशासनिक दृष्टि से अफसर निवेशकों को इतना उलझा देते कि निवेशक अपना प्रस्ताव वापस लेकर किसी दूसरे राज्य में जाकर निवेश करते।

ईज ऑफ डूइंग सिस्टम हुआ फेल

मोहन सरकार लगातार दावा कर रही है कि उन्होंने सुशासन व्यवस्था को प्रदेश में बेहतर ढंग से लागू किया है। लेकिन उनका यह दावा पूरी तरह से खोखला दिखाई पड़ रहा है। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले एक साल से मोहन सरकार ने जो भी निवेश लाने का दावा किया उनमें से कंपनी और उसके प्रतिनिधि को यहां इंडस्ट्री लगाने के लिये ली जाने वाली जरूरी अनुमतियां अब तक नहीं मिली हैं। यही कारण है कि निवेश धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है।

क्या प्रधानमंत्री की संकल्पना रहेगी अधूरी?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनने के लिये कह रहे हैं। लेकिन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनके करीबी अफसरों की उदासीनता के कारण प्रधानमंत्री की यह संकल्पना अधूरी दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि जिस उद्योग विभाग से निवेशकों को जरूरी अनुमतियां मिलनी थी उस विभाग में सात महीने तक कोई सचिव स्तर का अधिकारी ही नहीं नियुक्त किया गया। ऐसे में सभी ठंडे बस्ते में चली गई। अब जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है उससे ठीक पहले मोहन सरकार ने अपने चहेते अफसर को उद्योग विभाग के सचिव का दायित्व देते हुये सभी पेंडिंग फाइलों को क्लीयर करने के आदेश दिये। वहीं प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण मंडल में 50 दिनों तक अध्यक्ष पद रिक्त होने के कारण किसी उद्योग को जरूरी पर्यावरण अनुमति concent to establish नहीं दी गई थी।

इन दावों की खुली पोल

40 फीसदी तक दी जा रही है सब्सिडी

औद्योगिक विकास निगम के अधिकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के जरिए नए उद्योगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। यहां पर उद्योग खोलने की अनुमति लेने के लिए अधिक चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए उद्योगों को अनुमति मिलेगी। इसके अलावा उद्योगों को आकर्षित करने के लिए 40 फीसदी तक की सब्सिडी भी सरकार की ओर से दी जा रही है। जबकि हकीकत बिल्कुल इससे अलग है। न तो सिंगल विंडो सिस्टम ठीक से काम कर रहा है और न ही लोगों को सब्सिडी का फायदा मिल रहा है।

जमीन का होगा ऑनलाइन एलॉटमेंट

सरकार की ओर से नए उद्योग लगाने को लेकर भी पूरी पारदर्शिता के साथ नई नीति के तहत काम किया जा रहा है। सरकार की ओर से इसे पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया गया है। उद्योगपतियों को सारी औपचारिकता निभाने के बाद 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन अलॉटमेंट हो सकता है। इसके बाद में नए उद्योग का कार्य शुरू कर सकते हैं। यह सुविधा मध्यप्रदेश सरकार की ओर से काफी सरलीकरण के साथ उद्योगपतियों के बीच प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले एक साल से जिन उद्योगपतियों ने जरूरी अनुमतियों के लिये आवेदन किया था उन्हें अभी तक जरूरी अनुमति नहीं मिली और न ही जमीनों का अलॉटमेंट हुआ।

कलेक्टर ने शमशाबाद क्षेत्रों के ग्रामों का भ्रमण कर जायजा लिया

-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह. विदिशा। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने शमशाबाद तहसील क्षेत्र के ग्रामों का भ्रमण कर निर्माण कार्यों तथा शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की अद्यतन जानकारियां प्राप्त की। उन्होंने भ्रमण क्षेत्रो में स्थानीय ग्रामीणजनों से संवाद कर योजनाओं के क्रियान्वयन की क्रास मानिटरिंग की है। कलेक्टर सिंह ने भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित कार्यों का विशेष तौर पर जायजा लिया है। कलेक्टर सिंह ने भ्रमण निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित दो अधिकारियों को टेलीफोन के माध्यम से बुलाने का संदेश प्रेषित कराया था इसके बावजूद उपस्थित नहीं होने पर उक्त दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित रहे सर्वशिक्षा अभियान के संविदा उपयंत्री आशीष जैन

की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश डीपीसी को दिए है। गौरतलब हो कि भ्रमण के दौरान और शालाओं की मरम्मत कार्यों में कोई रूचि नहीं लेने पर आशीष जैन की सेवा समाप्ति की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के नटेरन परियोजना अधिकारी राजेश जैन के खिलाफ निलंबन कार्यवाही का प्रस्ताव संभागायुक्त को प्रेषित करने की कार्यवाही क्रियान्वित करने के निर्देश जनपद सीईओ को दिए गए है। कलेक्टर सिंह ने ग्राम वर्धा के धाकड़ मोहल्ले में एक करोड़ की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय सीमा अवधि मार्च माह तक पूर्ण कराने के निर्देश निर्माण ऐजेन्सी आरईएस के कार्यपालन यंत्री को दिए है। कलेक्टर सिंह ने वर्धा के पीएमश्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पहुंचकर शैक्षणिक गतिविधियों का जायजा लिया है। यहां उन्होंने स्कूली विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी शैक्षणिक तर्क शक्तियों को प्रश्नोत्तरी संवादों के माध्यम से जाना है। उन्होंने कुछ विद्यार्थियों को बिना यूनिफार्म के उपस्थित पाए जाने पर उनसे ड्रेस के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान डीपीसी आरपी लखेर ने बताया कि पीएमश्री विद्यालयों में ब्लेजर की राशि शिक्षकों को आवंटित की गई है जबकि ड्रेस की राशि बच्चों के द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिभावकों के बैंक खातो में 600-600 रूपए जमा किए गए हैं।

होनहार छात्रों को लेपटॉप कब?

-बद्री प्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। प्रदेश सरकार प्रति वर्ष एसे छात्रों को जिन्होंने 12 की परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं उन्हें 25 हजार रुपये की राशि लेपटाप खरीदने के लिए प्रदान करती हैं लेकिन इस वर्ष अब तक यानी 31 जनवरी तक यह राशि छात्रों को नहीं मिल पाई है। पूरा शिक्षण सत्र समाप्त होने की कागार पर है। लेकिन होनहार छात्रों के हाथ खाली हैं। उनकी उच्च शिक्षा में बाधा पड़ रही है। अभिभावक कर्ज लेकर लेपटाप खरीदने को मजबूर हैं। ऐसे में पूरी योजना सवालों के घेरे मे है। नरसिंहपुर जिले के करीब लगभग 200 से लेकर 300 छात्रों के अभिभावक परेशान हैं। जानकारों का कहना हैं कि प्रदेश के लाखों छात्र इस महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित हैं। कालेजों में लेपटाप अनिवार्य होता है। इन्जीनियर, मेडिकल, कामर्स, एलएलबी के सभी छात्रों को अनिवार्य होता है। मगर लाभ से वंचित हैं। जो छात्र गरीब हैं लेपटाप नहीं हैं उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। अधिकारियों ने फंड की कमी बताई है। उनका कहना है सरकार की तरफ से कोई पत्र नहीं आया है।

युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए गुणवत्ता पूर्ण भोजन, शिक्षा एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना हम सब की प्राथमिकता: राज्यपाल श्री रमेन डेका

ऊर्जा से भरे प्रतिभाशाली युवाओं के सहयोग से होगा विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। देश के लगभग 30 करोड़ बच्चे और युवा विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस समूह के उज्जवल भविष्य के लिए गुणवत्ता भोजन, शिक्षा एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना हम सभी की प्राथमिकता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम खोले गए हैं, जिसमें डिग्री के साथ कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है। भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह उद्गार राज्यपाल रमेन डेका एवं कुलाधिपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में व्यक्त किये। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 10 वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने से पूर्व विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर उनका पुण्य स्मरण किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजिनियरिंग एण्ड बायोटेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक डॉ. वांगा शिवा रेड्डी विशेष रूप से उपस्थित थे। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के सभागार में आयोजित भव्य एवं

गरिमामय दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 तक उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पदक एवं उपाधियां वितरित की गई। मेधावी विद्यार्थियों को 16 स्वर्ण, 18 रजत एवं 4 कास्य पदक प्रदान किए गए। साथ ही लगभग 4200 विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पी.एच.डी की उपाधि प्रदान की। कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन में राज्यपाल रमेन डेका ने उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपने अपनी कड़ी मेहनत से अध्ययन कर ये मेडल प्राप्त किए हैं। आपके जीवन की यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस विश्वविद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त की है, उसका उपयोग आप समाज एवं देश के कल्याण एवं विकास के लिए करेंगे तथा दूसरों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बनेंगे। श्री डेका ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना प्रस्तुत की है एवं हम सबको इसे प्राप्त करने के लिए लगातार कार्य करना है। वर्तमान में हम सभी प्रकार के भोजन, अनाज, तिलहन, सब्जी, फल, दूध, मांस, मछली आदि के साथ लगभग 1000 मिलियन टन भोजन का उत्पादन कर रहे हैं। वर्ष 2047 तक इसे 1500 मिलीयन टन तक बढ़ाना होगा। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। बदलते मौसम एवं बाजार के उतार चढ़ाव से कृषि में जोखिम बढ़ गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या युवाओं की है। देश एवं प्रदेश की प्रगति में भी युवा शक्ति का भी उल्लेखनीय योगदान है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप मुझे देश के 100 ऊर्जावान युवा दे दें, मैं देश के भविष्य को बदल दूंगा। आज भारत के पास ऊर्जा से भरी युवाओं की पीढ़ी है, निश्चय ही हम स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को पूरा करने की दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है और इसे पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। विकसित भारत के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। ऊर्जा से भरे प्रतिभाशाली युवाओं के बूते निश्चित ही हम विकसित छत्तीसगढ़ के सपनों को मूर्त रूप प्रदान करेंगें। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आधुनिक युग विज्ञान एवं तकनीक का युग है। आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान एवं तकनीक का उपयोग समाज के हित में, देश एवं प्रदेश के विकास में करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़वासियों की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए पूर्ण समर्पण से कार्य करें और विकसित छत्तीसगढ़ गढ़ने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। दीक्षांत समारोह में विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रबंध मण्डल तथा विद्या परिषद के सदस्यगण, प्राध्यापक, वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय के अधिकारी, उपाधि तथा पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी तथा उनके पालकगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन

-आनंद शर्मा

जगत प्रवाह. रायपुर।आनंद शर्मा, संवाददाता

रायपुरः मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महात्मा गांधी की 30 जनवरी को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने महात्मा गांधी सहित देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि शहीद दिवस उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को याद करने का अवसर है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इन वीर बलिदानियों का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। भारत की आजादी के लिए महात्मा गांधी जी के अतुलनीय योगदान को याद करते हुए श्री साय ने कहा कि गांधीजी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी के विचार आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हम सभी गांधी जी के बताए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का प्रण लें और राष्ट्र के विकास में योगदान दें।

परधान समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. हरदा। कृषि उपज मंडी प्रांगण हरदा में आदिवासी परधान समाज के भगवान हीरसुखा पाटालीर का जन्मोत्सव के अवसर पर परधान समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन सम्पन्न हुआ जिसमें समाज के 148 युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। इस अवसर पर विभिन्न विधाओं में जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर चयनित प्रतिभाशाली युवक युवतियों को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ धरती के प्रथम संगीत गुरु हीरा सुखा का पूजन (गोगो पाठ) किया जाकर महुआ माला अर्पित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परधान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुठवाल के.पी. प्रधान, विशेष अतिथि प्रदेश अध्यक्ष राकेश परते, डॉ. अशोक मसकोले पूर्व विधायक निवास एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता संभागीय अध्यक्ष रमेश मसकोले द्वारा की गई। तेलंगान से आई महिला टीम द्वारा आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बसंत कबडे, जिलाध्यक्ष नर्मदापुरम बादामीलाल आहके, जिलाध्यक्ष बैतूल अशोक मसकोले, जिलाध्यक्ष हरदा रामभरोस भलाबी, संजय प्रधान, जय किशन मरकाम, नागेश परते, नानक राम उईके, गौतम धुर्वे, अनिल परते, शुभम इवने, सौरभ भलावी, अजय तुमराम, अशोक मसकोले, ललित परधान, दिनेश प्रधान, महेश भलावी, रेखा मसकोले, शिल्पा प्रधान, सुषमा प्रधान, मनुबाई परते, ममता प्रधान, किरण कुमरे, सहित मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, व तेलंगाना चार राज्यों के पदाधिकारी व समाजिक कार्यकर्ता साथी गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन धनसिंह भलावी एवं हरपाल धुर्वे द्वारा किया गया।

छात्रा ने सीपीआर देकर बचाई शिक्षक की जान

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमुनिया चिखली की छात्रा निशिका यादव व प्रतीक्षा विश्वकर्मा ने मिलकर शिक्षक महिपाल ठाकुर प्राथमिक शिक्षक की सीपीआर देकर जान बचाई। शालेय कार्यक्रम के पश्चात शिक्षक को शाला में ही हार्ट अटैक आ गया। इस पर स्कूली छात्रा निशाका और प्रतीक्षा ने शिक्षक महिपाल ठाकुर को सीपीआर दिया। स्कूली छात्राओं ने बताया कि जब उन्होंने शिक्षक को देखा तो ना तो उनकी नाडी चल रही थी और न ही वे सांस ले रहे थे। तब छात्राओं ने सीपीआर दिया सीपीआर देने की पश्चात शिक्षक की सांस पुनः चलने लगी। जब तक एंबुलेंस आई और एंबुलेंस आने के बाद शिक्षक को देवरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पर उनका उपचार किया गया। पूरे घटना क्रम की जानकारी जब डॉक्टर की टीम को बताई तो उन्हें बहुत खुशी हुई बहुत और उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के लाभ को जनता तक पहुंचाने का अभिवादन किया। चूंकी है छात्राएं व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत अध्यनरत हैं और कुछ समय पूर्व देवरी के वरिष्ट डॉ. राहुल बारोलिया व डॉ रूपेश ठाकुर व गोविंद बर्दिया ने छात्राओं को सीपीआर के संबंध में प्रशिक्षण दिया था। छात्रा निशिका यादव और प्रतीक्षा विश्वकर्मा के द्वारा भी ट्रेनिंग ली गई थी।

सम्पादकीय

यमुना में जहर का सच सामने लाकर फंसे केजरीवाल

दिल्ली और पंजाब में आआपा पार्टी की सरकारों के रहते कभी अरविंद केजरीवाल एवं भगवंतसिंह मान ने यह दावा किया था कि कि यमुना नदी में लंदन की टेम्स नदी की तर्ज पर स्वच्छ पानी बहेगा, लेकिन उनका यह दावा पूरी तरह खोखला साबित हुआ। इसके बाद अब दिल्ली चुनाव के चलते बड़बोले केजरीवाल ने यमुना नदी में जहर होने की बात कहकर सबको अचरज में डाल दिया है। इस मामले में चुनाव आयोग द्वारा दिए नोटिस के बाद वह बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं यमुना में जहर मिलाने के केजरीवाल के आरोपों पर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जमकर हमला बोला है। सहने रोहिणी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्लीवासियों को दूषित पानी पीने को मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि चुनाव के लिए झूठ बोलना बंद करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा से यमुना के जल में जहर किसने मिलाया है इसके सबूत पेश करें। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायबसिंह सैनी ने अनोखे अंदाज में जवाब दिया है। मुख्यमंत्री सैनी ने दिल्ली-हरियाणा सीमा पर दहिसरा गांव के पास यमुना नदी के 'पॉइंट नंबर-4' का दौरा किया और पूजा-अर्चना कर यमुना के जल का आचमन किया। सैनी ने इसके बाद कहा कि जहर इस पवित्र नदी में नहीं बल्कि विपक्ष के दिमाग में भरा है। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल झूठ की राजनीति कर रहे हैं। यमुना के पानी में 'जहर मिलाने' वाला उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण बयान देने के लिए अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए।' नायबसिंह सैनी की आचमन करने की तस्वीरें सामने आई तो केजरीवाल ने ट्विट कर इसे ढोंग बताया। केजरीवाल ने कहा कि सच तो ये है कि उन्होंने यमुना का पानी पिया ही नहीं। केजरीवाल ने लिखा कि हरियाणा सरकार उनके खिलाफ केस करना चाहती है तो करे लेकिन जिस जहरीले पानी को नायब सैनी खुद नहीं पी सकते उसे वह दिल्ली के लोगों को किसी भी कीमत पर पीने नहीं देंगे। कुलमिलाकर दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आआपा के मुखिया अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ उन्हें चुनाव आयोग में जवाब दाखिल करना है और दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने उन पर एफआईआर दर्ज कराने का फैसला ले लिया है। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा दिए गए नोटिस का अरविंद केजरीवाल ने जो जवाब दिया है उससे आयोग संतुष्ट नहीं है। आयोग ने नोटिस पर केजरीवाल के जवाब को असंतुष्टि जाहिर करते हुए उन्हें जवाब के लिए पुनः पत्र लिखा है। जिसमें कहा गया है कि उनका जवाब सार्वजनिक और बहुचर्चित वक्तव्य के बारे में बिल्कुल खामोश है, जिसमें जलापूर्ति को विषाक्त करने की बात कही गई है। दूसरी ओर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने उनके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सोनीपत में सीजेएम के न्यायालय में डिजस्टर मैनेजमेंट की धारा 2डी, 154 के तहत केस दर्ज कराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने प्रदेश और दिल्ली के लोगों में पैनिक फैलाने का काम किया है। इसी के साथ सोनीपत के न्यायालय तक यह मामला पहुंच गया है जिसमें 17 फरवरी को सुनवाई होगी।

सियासी गहमागहमी

जीतू का एक्सीडेंट, किसी की साजिश तो नहीं

बीते सप्ताह प्रदेश के राजनीतिक से जुड़े नेताओं के लिए बड़ा अजीब रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक्सीडेंट हो गया वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ भी एक्सीडेंट की घटना हुई। दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुई घटना के बाद सियासी गलियारे में खबरें उड़ने लगी हैं कि यह दुर्घटना है या फिर कोई साजिश। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस जब इस पूरे मामले की जांच करेगी तो क्या सामने निकलकर आता है। खैर कुछ लोगों ने इसे आपसी राजनीतिक रंजिश भी करार दिया है।

मुख्यमंत्री का अगला विदेशी दौरा कहा है

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पिछले कुछ महीने से प्रदेश में निवेश लाने के उद्देश्य से विदेश यात्रा कर रहे हैं। उनकी इस यात्रा के मद्देनजर मंत्रालय के गलियारे में अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर खासी चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री अगला विदेशी दौरा कब बना रहे हैं। हर अफसर उनके साथ विदेश यात्रा करने के लिए उत्साहित हैं और लगातार इसके लिए वह प्रयास भी कर रहा है। चर्चा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि इस बार जब मुख्यमंत्री विदेशी दौरे पर जाए तो उनके साथ सचिव स्तर के कुछ और अधिकारी भी शामिल हो। अब देखने वाली बात यह है कि आईएएस अफसरों की यह मंशा कब पूरी होती है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

केजरीवाल जी यह साफ-साफ क्यों नहीं कहते कि वह दिल्ली में जाति जनगणना करवाएंगे और आरक्षण को 50% से ज्यादा बढ़ाएंगे?

मैं गारंटी देता हूं कि केजरीवाल जी ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी मोदी जी की तरह
आरक्षण के खिलाफ हैं
गरीबों के खिलाफ है
दलितों के खिलाफ है...

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

सत्य-अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजली और भावपूर्ण नमन।

देशभक्तों का कर्तव्य है कि गांधी जी के विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।

शहीद दिवस पर बापू को नमन।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

कानूनी प्रतिभा के पर्यायवाची रहे हैं राम जेठमलानी

समता पाठक/जगत प्रवाह

राम जेठमलानी, कानूनी प्रतिभा और अडिग वकालत के पर्यायवाची नाम, भारत के सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद वकीलों में से एक थे। उनका जन्म 14 सितंबर 1923 को शिकारपुर, सिंध (अब पाकिस्तान में) में हुआ था। उनकी प्रतिभा सिर्फ अदालतों तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा, उनका जीवन विविध अनुभवों से भरा था जो युवा वकीलों और अधिवक्ताओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं। 8 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। राम जेठमलानी ने 17 वर्ष की आयु में कानून में स्नातक की डिग्री पूरी की और 18 वर्ष की आयु में बार काउंसिल में नामांकन कराया। उन्होंने वरिष्ठ वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट में अपने मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कई बार राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री भी रहे। जेठमलानी को राष्ट्रीय सुर्खियों में लाने वाले शुरुआती हाई-प्रोफाइल मामलों में से एक कुख्यात नानावटी मामला था। नौसेना कमांडर केएम नानावटी पर एक व्यवसायी की हत्या का मुकदमा चलाया गया, जिस पर उन्हें अपनी पत्नी के साथ संबंध होने का संदेह था। व्यवसायी का बचाव राम जेठमलानी ने किया। इस मामले ने न केवल जेठमलानी के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, बल्कि कानूनी प्रणाली पर भी इसका स्थायी प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः भारत में जूरी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। राम जेठमलानी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे का बचाव किया था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान को अनुग्रहपूर्ण कार्य माना।

हर्षद मेहता सिक्योरिटीज घोटाला (1992)

राम जेठमलानी ने 70 मामलों में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपी कुख्यात स्टॉकब्रोकर हर्षद मेहता का प्रतिनिधित्व किया। जेठमलानी ने वित्तीय लेनदेन और विनियमनों के जटिल जाल को कुशलतापूर्वक सुलझाया। यद्यपि बाद में हर्षद मेहता की सजा बरकरार रखी गई, लेकिन राम जेठमलानी के बचाव ने वित्तीय प्रणाली और नियामक ढांचे में खामियों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

मनोहर जोशी बनाम नितिन भाऊराव पाटिल (1995)

यह मामला 'हिंदुत्व' शब्द की व्याख्या के इर्द-गिर्द घूमता था और यह भी कि क्या चुनाव प्रचार के दौरान इसका प्रयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण है। राम जेठमलानी ने तर्क दिया कि 'हिंदुत्व' एक जीवन पद्धति है, कोई धर्म नहीं, तथा राजनीतिक विमर्श में इसका प्रयोग वैध है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि 'हिंदुत्व' या 'हिंदूइज्म' शब्द किसी विशेष धर्म को संदर्भित नहीं करते, बल्कि एक जीवन शैली को शामिल करते हैं।

अरुण जेटली बनाम अरविंद केजरीवाल (2017)

राम जेठमलानी ने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दायर एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व किया था। कार्यवाही के दौरान, अपनी स्पष्टवादी और कभी-कभी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए जाने जाने वाले जेठमलानी ने जेटली के खिलाफ कठोर भाषा का प्रयोग करके सुर्खियां बटोरीं। इस मामले ने न केवल अपने कानूनी निहितार्थों के कारण बल्कि जिरह के दौरान अदालती घटनाक्रम के कारण भी ध्यान आकर्षित किया।

OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सक्रियता और प्रदेश के करोड़ों लोगों के सहयोग और विश्वास से मिली 27 प्रतिशत आरक्षण को हरी झंडी

तत्कालीन शिवराज सरकार और उनके मंत्रियों की कोर्ट को गुमराह करने की साजिश हुई नाकाम

-विजया पाठक

एक कहावत है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं... पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने प्रदेश में जिस 27 प्रतिशत आरक्षण की संकल्पना की थी वह अब पूरी होती दिखाई दे रही है। पिछले दिनों प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में जो चुनौती दी गई थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और इस तरह से कमलनाथ के 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का प्रण पूरा होता दिखाई दे रहा है। जाहिर है कि लोकप्रिय और पिछड़ा वर्ग के युवाओं के हितैषी रहे कमलनाथ ने पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रदेश में वर्ष 2018 में सत्ता संभालने के साथ ही आरक्षण का मुद्दा उठाया था। लेकिन तत्कालीन विपक्षी दल और भाजपा के नेता शिवराज सिंह चौहान ने आरक्षण का विरोध करते हुए इस पूरे मामले को कोर्ट तक पहुंचा दिया। एक के बाद एक कोर्ट में वर्तमान सरकार द्वारा इस पूरे मुद्दे को अमित करने का कार्य किया जाता रहा लेकिन कोर्ट ने भाजपा नेताओं और प्रदेश सरकार की एक नहीं सुनी और मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के फैसले को हरी झंडी दे दी। आरक्षण को लागू करने की जो हरी झंडी प्रदेश को मिली है वह करोड़ों युवाओं के प्रेम, सहयोग और कमलनाथ के सक्रियता का प्रमाण है। अगर कमलनाथ ने सत्ता हाथ से चले जाने के बाद खुद को शांत कर दिया होता तो शायद आज भी यह विषय कोर्ट की फाइलों में दबा रहता। लेकिन कमलनाथ ने प्रदेशवासियों से किए वादे को निभाने के लिए सक्रियता बनाए रखी और विजय हासिल की।

मार्च 2019 में कमलनाथ ने उठाया था विषय

मध्य प्रदेश में 2018 तक अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण मिलता था। 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले ही मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग कई बार उठ चुकी थी। ओबीसी नेताओं का दावा था कि मध्य प्रदेश में उनकी आबादी 51% है इसलिए उन्हें 14% से बढ़कर 27% आरक्षण मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर राजनीति कर रही थीं। लेकिन कांग्रेस के वादे पर भरोसा जताते हुए ओबीसी वर्ग ने कांग्रेस को जमकर समर्थन दिया और उनकी वजह से कमलनाथ सरकार में आ पाए। सरकार में आने के बाद कमलनाथ ने अपना वादा निभाया और उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग

यह कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है: कमलनाथ

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण देने के फैसले का विरोध किया गया था। यह कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है। मार्च 2019 में मैंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में मध्य प्रदेश के ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। हाई कोर्ट के फैसले ने मेरी तत्कालीन सरकार के निर्णय को एक बार फिर सही साबित किया है। अब मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल सभी स्तर पर 27% ओबीसी आरक्षण देना सुनिश्चित करना चाहिए। ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा ने हमेशा षड्यंत्रकारी रवैया अपनाया है। अगर पिछले 06 साल के घटनाक्रम को देखें तो यह बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। (शेष पेज 7 पर)

कमलनाथ
(मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ नेता)

विकास के लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण होना जरूरी, आज देश को छिंदवाड़ा मॉडल जैसी सोच की जरूरत

निश्चित रूप से आज के भारत में और 75 साल पहले के भारत में काफी अंतर है। भारत ने अनेकों क्षेत्रों में विकास को परिभाषित किया है। आज हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। विकास के इस चक्र में किसी विशेष पार्टी या राजनीतिक दल को श्रेय नहीं दिया जा सकता है। देश के हर एक देशवासी का भी उतना ही योगदान है जितना कि हमारे जनप्रतिनिधियों का है, सरकारों का है। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं। पिछले चार दशकों से समाजसेवा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। विकास को लेकर मेरा मानना है कि हमें हमेशा भविष्य को ध्यान में रखकर सोचना चाहिए। बदलती तकनीक, आने वाली जरूरतें, वैश्विक परिदृश्य और नए अवसरों को समझते हुए विकास की योजना बनानी चाहिए। हमारा लक्ष्य सिर्फ विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित करना होना चाहिए। मैं यहां छिंदवाड़ा के विकास मॉडल की चर्चा करना चाहूंगा। छिंदवाड़ा के विकास मॉडल की सारे विश्व में चर्चा होती है। चर्चा का यह विषय अनायास नहीं नहीं बना है। इसके लिए मैंने दूरदृष्टि सोच को प्राथमिकता में रखा। इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य था कि मैं सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए एक दूरगामी विजन तैयार करूं और उस पर अमल करूं। मैंने वैसा ही किया। विकास के हर पहलू पर ध्यान दिया। जिससे कि न केवल क्षेत्र विकसित हो बल्कि वहां के निवासियों को भी महसूस हो कि हमारा जीवन बेहतर हो गया है। रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास ऐसा जाल बिछाया कि आज अन्य जगहों से लोग छिंदवाड़ा में रोजगार पा रहे हैं।

आज देश के हर एक जिले को छिंदवाड़ा के विकास मॉडल की जरूरत है। उस क्षेत्र के सांसद और विधायक को इसी मॉडल पर जोर देना होगा। क्योंकि देश का हर जिला विकसित हो गया तो पूरा देश ही विकसित हो जायेगा। जिला विकसित हुआ तो देश-विदेश से निवेश आयेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका जीवन बेहतर होगा। राजनेता अपने माध्यम से बड़े-बड़े उदयोगों को अपने जिले में स्थापित कर सकते हैं। सीएसआर के माध्यम से भी काफी हद तक लोगों को रोजगारोन्मुखी किया जा सकता है। इसके लिए बहुत कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। केवल सोच सकारात्मक रखकर हम जिले को विकसित कर सकते हैं। यदि सांसद-विधायक इसी सोच के साथ काम करेंगे तो निश्चित ही सही मायने में यही समाजसेवा का एक प्रकल्प होगा।

मैंने छिंदवाड़ा में इसी दृष्टिकोण के साथ काम किया है। पिछले चार दशकों में हमने छिंदवाड़ा को एक नया रूप दिया है। हमने न केवल बुनियादी ढांचे का विकास किया है, बल्कि शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास पर भी जोर दिया है। हमारा लक्ष्य था कि छिंदवाड़ा के युवाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए एक मजबूत आधार मिले।

मेरी सोच हमेशा यही रही है कि विकास का मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसमें जनकल्याण समाहित हो। बगैर भेदभाव और जात-पात के विकास को आधार बनाया है। विकास में दूरदृष्टि का होना बहुत जरूरी है। जिसमें अधोसंरचना के साथ-साथ क्षेत्र की जनता का भी ध्यान रखना होगा। वह चाहे क्षेत्र कोई सा भी हो। उद्योग, कृषि, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, निवेश और व्यापार जैसे बुनियादी मामलों पर विकासकर्ता की सोच हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। राजनीतिक द्वेष को जगह नहीं होना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता का कल्याण ही सर्वोपरि है। (शेष पेज 7 पर)

कुंभ प्रयाग में हादसा

आस्था का आवेग बना हादसे का कारण

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

प्रचार का प्रभाव और पर्व विशेष में त्रिवेणी में डुबकी लगाने के उत्साह में मची भगदड़ में तीस लोग प्राण गंवा बैठे और करीब 60 लोग घायल हो गए। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के विशेष पर्व स्नान का विशेष मुहूर्त था, करोड़ों लोग मुहूर्त की प्रतीक्षा की शुभ घड़ी में गंगा तट पर एकत्रित होते चले गए। यहीं रुकने और चादर बिछाकर सो भी गए। फिर जब अर्धरात्रि में एक से दो के बीच स्नान के लिए भीड़ का सैलाब उमड़ा तो रेत पर सोये लोगों की अनदेखी करते आगे बढ़े और लड़खड़ा कर एक-दूसरे पर गिरने लगे। इस उठापटक में संभलने का अवसर भी नहीं मिला और लोग हताहत होते चले गए। ऐसा नहीं था कि प्रशासन को इस तरह के संकट की आशंका न हो? क्योंकि पांच से लेकर 10 करोड़ लोगों के संगम में डुबकी लगाने की संभावना पूर्व से ही की जा रही थी। रात 9-10 बजे से ही यह अपील की जा रही थी कि लोग स्नान करते चलें और संगम स्थल से निकल जाएं। परंतु शुभ मुहूर्त के फेर में आस्थावान श्रद्धालु डटे रहे और सनातन के चरम पर पहुंचे कुंभ में अनहोनी घट गई। घटना से स्थितप्रज्ञ अधिकारियों का विवेक कुछ समझ ही नहीं पाया, नतीजतन आकस्मिक उपचार की सुविधाएं भी विलंब से पहुंची। साफ है, जब ऐसी परिस्थिति की आशंका थी, तब पहले से ही परिकल्पना करके उससे तत्काल निपटने के उपाय प्रशासन को संगम पर करने की जरूरत थी। प्रशासन का प्रबंधन जहां चकनाचूर था, वहीं भीड़ का अनुशासन भी नहीं दिखा। वस्तुतः आस्था के अनियंत्रित आवेग में खोते हुए विवेक ने घटना को अंजाम दे दिया। यहां जरूरत थी कि भीड़ को मेले में प्रवेश ही एक तय संख्या के समूह में क्रम-क्रम से दिया जाता। प्रशासन ने इसी मेले में गीता प्रेस के परिसर में आग लगने के बावजूद कोई सबक नहीं लिया।

भारत में पिछले डेढ़ दशक के दौरान मंदिरों और अन्य धार्मिक आयोजनों में उम्मीद से कई गुना ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। जिसके चलते दर्शन-लाभ की जल्दबाजी व कुप्रबंधन से उपजने वाली भगदड़ व आगजनी का सिलसिला हर साल इस तरह के धार्मिक मेलों में देखने में आ रहा है। इसी प्रयाग के 2013 में संपन्न हुए कुंभ मेले में रेलवे स्टेशन पर बने पैदल पुल पर भगदड़ मचने से 42 लोगों की मौत हो गई थीं। लेकिन प्रशासन ने इस घटना से कोई सबक नहीं लिया। 1954 में भी प्रयागराज के कुंभ में 3 फरवरी को मौनी अमावस्या पर भगदड़ मची और 800 लोग काल के गाल में समा गए। 1986 में हरिद्वार के कुंभ में वीआईपी दर्जे के लोगों को विशेष स्नान के लिए भीड़ रोक देने के कारण भगदड़ मची और 200 लोग मारे गए थे। 2003 के नासिक कुंभ में 39 और 2010 के हरिद्वार के कुंभ में शाही स्नान के दौरान भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। साफ है, प्रत्येक कुंभ में जानलेवा घटनाएं घटती रहने के बावजूद शासन-प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिए। धर्म स्थल हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम कम से कम शालीनता और आत्मानुशासन का परिचय दें। किंतु इस बात की परवाह आयोजकों और प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं होती, अतएव उनकी जो सजगता घटना के पूर्व सामने आनी चाहिए, वह अकसर देखने में नहीं आती? लिहाजा आजादी के बाद से ही राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र उस अनियंत्रित स्थिति को काबू करने की कोशिश में लगा रहता है, जिसे वह समय पर नियंत्रित करने की कोशिश करता तो हालात कमोबेश बेकाबू ही नहीं हुए होते? अतएव देखने में आता है कि आयोजन को सफल बनाने में जुटे अधिकारी भीड़ के मनोविज्ञान का आकलन करने में चूकते दिखाई देते है। वस्तुतः कुप्रबंधन को लेकर विपक्ष को आयोजन में कमियां उजागर करने का मौका मिल गया।

इस कुंभ की तैयारियों के लिए कई हजार करोड़ की धनराशि खर्च की गई। जरूरत से ज्यादा प्रचार करके लोगों को कुंभ स्नान के लिए आमंत्रित किया गया। फलतः कौने-कौने से श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाने का मन बना लिया। नतीजा यह निकला कि जिसे जो आवागमन का साधन मिला प्रयागराज की ओर चल दिया। जनसैलाब इतनी बड़ी संख्या में उमड़ा कि परिवहन से लेकर प्रयाग में प्रबंधन के सभी साधन कम पड़ गए। करोड़ों की भीड़ को संभालने के लिए सात स्तरीय सुरक्षा प्रबंधों से लेकर जो भी आधुनिक तकनीकि उपाय किए गए थे, वे सब ध्वस्त हो गए। ऐसा मेले के विराट रूप में बदल जाने के कारण हुआ। वैसे भी हमारे धार्मिक-आध्यात्मिक आयोजन विराट रुप लेते जा रहे हैं। कुंभ मेलों में तो विशेष पर्वों के अवसर पर एक साथ कई करोड़ लोग एक निष्चित समय के बीच स्नान करते हैं। ऐसे में भीड़ के अनुपात में यातायात और सुरक्षा के इंतजाम देखने में नहीं आते। जबकि शासन-प्रशासन के पास पिछले पर्वों के आंकड़े और अनुभव होते हैं। बावजूद लापरवाही और बदइंतजामी सामने आना चकित करती है। दरअसल, कुंभ या अन्य मेलों में जितनी भीड़ पहुंचती है और उसके प्रबंधन के लिए जिस प्रबंध कौशल की जरुरत होती है, उसकी दूसरे देशों के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते? इसलिए हमारे यहां लगने वाले मेलों के प्रबंधन की सीख हम विदेशी साहित्य और प्रशिक्षण से नहीं ले सकते? क्योंकि दुनिया के किसी अन्य देश में किसी एक दिन और विशेष मुहूर्त के समय लाखों-करोडों की भीड़ जुटने की उम्मीद ही नहीं की जाती? बावजूद हमारे नौकरशाह भीड़ प्रबंधन का प्रशिक्षण, लेने खासतौर से यूरोपीय देशों में जाते हैं। प्रबंधन के ऐसे प्रशिक्षण विदेशी सैर-सपाटे के बहाने हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे प्रबंधनों के पाठ हमें खुद अपने देशज ज्ञान और अनुभव से लिखने होंगे।

प्रशासन के साथ हमारे राजनेता, उद्योगपति, फिल्मी सितारे और आला अधिकारी भी धार्मिक लाभ लेने की होड़ में व्यवस्था को भंग करने का काम करते हैं। इनकी वीआईपी व्यवस्था और यज्ञ कुण्ड अथवा मंदिरों में मूर्तिस्थल तक हो हर हाल में पहुंचने की रूढ़ मनोदशा, मौजूदा प्रबंधन को लाचार बनाने का काम करती है। नतीजतन भीड़ ठसाठस के हालात में आ जाती है। ऐसे में कोई महिला या बच्चा गिरकर अनजाने में भीड़ के पैरों तले रौंद दिया जाता है और भगदड़ मच जाती है। इस कुंभ में जहां केंद्रीय मंत्रीमंडल के मंत्री स्नान के लिए आते रहे, वहीं भाजपा षासित प्रदेष सरकारों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने भी वीआईपी घेरे में श्रद्धालुओं को परे करके डुबकी लगाई। गौतम अडाणी ने भी परिवार सहित वीआईपी स्नान किए।

दरअसल दर्शन-लाभ और पूजापाठ जैसे अनुष्ठान अशक्त और अपंग मनुष्य की वैषाखी हैं। जब इंसान सत्य और ईश्वर की खोज करते-करते थक जाता है और किसी परिणाम पर भी नहीं पहुंचता है तो वह पूजापाठों के प्रतीक गढ़कर उसी को सत्य या ईश्वर मानने लगता है। यह मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी है। यथार्थवाद से पलायन अंधविश्वास की जड़ता उत्पन्न करता है। भारतीय समाज में यह कमजोरी बहुत व्यापक और दीर्घकालीक रही है। जब चिंतन मनन की धारा सूख जाती है तो सत्य की खोज मूर्ति पूजा और मुहूत्र्त की शुभ घड़ियों में सिमट जाती है। जब अध्ययन के बाद मौलिक चिंतन का मन-मस्तिष्क में ह्रास हो गया तो मानव समुदाय भजन-कीर्तन में लग गया। यही हश्र हमारे पथ-प्रदर्शकों का हो गया है। नतीजतन पिछले कुछ समय से सबसे ज्यादा मौतें भगदड़ की घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में उन श्रद्धालुओं की हो रही हैं, जो ईश्वर से खुशहाल जीवन की प्रार्थना करने धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं।

भीड़ बढ़ाने में मीडिया की भूमिका

धार्मिक स्थलों पर भीड़ बढ़ाने का काम मीडिया भी कर रहा है। प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के साथ सोशल मीडिया भी टीआरपी के लालच में अहम् भूमिका निभाता नजर आ रहा है। इस कुंभ में हम देख रहे है कि नीली आंखों वाली लड़की और आईआईटिअन साधु के वीडियो एक तमाशे के रूप में कहीं ज्यादा दिखाए और देखे गए है। जबकि शंकराचार्यों से धर्म और आस्था के गूढ़ रहस्यों को ज्ञात करने की जरूरत थी? परंतु हमारे यहां प्रत्येक छोटे बड़े मंदिर के दर्शन को चमात्कारिक लाभ से जोड़कर देश के भोले-भाले भक्तगणों से एक तरह का छल मीडिया कर रहा है। इस मीडिया के अस्तित्व में आने के बाद धर्म के क्षेत्र में कर्मकांड और पाखण्ड का आडंबर जितना बड़ा है, उतना पहले कभी देखने में नहीं आया। इसकी पृष्ठभूमि में बाजारवाद की भूमिका भी रहती है। निर्मल बाबा, कृपालू महाराज, आशाराम बापू और रामपाल जैसे संतों का महिमामंडन इसी मीडिया ने किया था। हालांकि यही मीडिया पाखंड के सार्वजनिक खुलासे के बाद मूर्तिभंजक की भूमिका में भी खड़ा हो जाता है। मीडिया का यही नाट्य रूपांतरण अलौकिक कलावाद, धार्मिक आस्था के बहाने व्यक्ति को निष्क्रिय व अंधविश्वासी बनाता है। यही भावना मानवीय मसलों को यथास्थिति में बनाए रखने का काम करती है और हम ईश्वरी अथवा भाग्य आधारित अवधारणा को भाग्य और प्रतिफल व नियति का कारक मानने लग जाते हैं। दरअसल मीडिया, राजनेता और बुद्धिजीवियों का काम लोगों को जागरूक बनाने का है, लेकिन निजी लाभ का लालची मीडिया, लोगों को धर्मभीरू बना रहा है। राजनेता और धर्म की आंतरिक आध्यात्मिकता से अज्ञान बुद्धिजीवी भी धर्म के छद्म का शिकार होते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि पिछले दो दशक के भीतर मंदिर हादसों में लगभग 5000 से भी ज्यादा भक्त मारे जा चुके हैं। बावजूद श्रद्धालु हैं कि दर्शन, आस्था, पूजा और भक्ति से यह अर्थ निकालने में लगे हैं कि इनको संपन्न करने से इस जन्म में किए पाप धुल जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। गोया, पुनर्जन्म हुआ भी तो श्रेष्ठ वर्ण में होने के साथ आर्थिक रूप से समृद्ध व वैभवशाली होगा। परंतु इस तरह के खोखले दावों का दांव हर मेले में ताश के पत्तों की तरह बिखरता दिखाई दे रहा है। जाहिर है, धार्मिक दुर्घटनाओं से छुटकारा पाने की कोई उम्मीद निकट भविष्य में दिखाई नहीं दे रही है?

वसंत पंचमी: एक नई शुरूआत का उत्सव

पुरानी आदतों को बदलकर बनें खुद का बेहतर वर्जन

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

वसंत पंचमी का आगमन, प्रकृति का अद्भुत नज़ारा, एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह वह समय है जब प्रकृति अपने पुराने स्वरूप को त्यागकर नए पत्तों, फूलों से सजती है। पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं और नई कोंपलें फूटती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे जीवन में पुराने विचारों और आदतों को छोड़कर नई सोच और नई ऊर्जा का संचार होता है। वसंत पंचमी, हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है. यह त्योहार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है. इसे सरस्वती जयंती भी कहते हैं। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि परिवर्तन जीवन का अटूट हिस्सा है। जैसे पतझड़ के बाद वसंत आता है, वैसे ही असफलता के बाद सफलता भी आती है। हमें कभी भी अपने जीवन से हार नहीं माननी चाहिए। हर रात के बाद सुबह होती है, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है।

कई बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, उम्मीदें टूट गई हैं, निराशा हावी हो गई है। लेकिन याद रखिए, हर अंधेरे के बाद उजाला है। वसंत पंचमी हमें यही याद दिलाती है कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, अपने लक्ष्यों के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।

यह सच है कि जीवन में बदलावों को स्वीकार करना आसान नहीं होता। पुरानी सोच, पुरानी आदतें हमें जकड़े रहती हैं। लेकिन जो लोग बदलावों से डरते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, नई चीजें सीखनी होंगी, नई चुनौतियों का सामना करना होगा। अपने आप का बेहतर वर्जन बनने के लिए, सबसे पहले अपनी पुरानी सोच और आदतों को पहचानें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। फिर नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। नई किताबें पढ़ें, नए कोर्स करें, नए लोगों से मिलें। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। जीवन में कई बार असफलताएं आएंगी, लेकिन कभी हार न मानें। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें।

ज्ञान और शिक्षा का महत्व दर्शाती है सरस्वती जयंती

वसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर, आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लें और एक नई शुरुआत करें।

यह भी याद रखें कि वसंत पंचमी को ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इसलिए, यह त्योहार हमें ज्ञान और शिक्षा के महत्व को भी याद दिलाता है। हमें अपने जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। ज्ञान ही हमें सफलता की ओर ले जाता है।

यह त्योहार हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें अपने आसपास की सुंदरता का आनंद लेना चाहिए और अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। खुश रहने से हम स्वस्थ और ऊर्जावान रहते हैं। खुश रहने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सफल होते हैं। आइए इस वसंत पंचमी पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक रहेंगे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, कभी भी हार नहीं मानेंगे, हमेशा सीखते रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखेंगे।

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

राजनीतिक दलों को पर्यावरण के मुद्दों पर जवाबदेह बनाना जरूरी है

दिल्ली विधानसभा चुनाव जल्द होने वाला है। हर चुनाव किसी न किसी मुद्दे पर लड़ा जाता है। गरीबी, बेरोजगारी, विकास, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पिछले छः दशकों से मुद्दा रहा है। लेकिन दिन प्रति दिन पर्यावरणीय क्षरण का मुद्दा कभी भी न सरकार और न जनता के लिए गंभीर मुद्दा रहा। दिखावे के लिए थोड़ी बात जरूर करते हैं लेकिन इच्छा शक्ति नहीं दिखती। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण आम लोग परेशान हैं। पर्यावरणविद इस मुद्दे पर पर सरकारों लगातार घेरते रहे हैं। प्रदूषण की समस्या दिल्लीवासियों के जीवन के स्वास्थ्य जोखिम में डाल रही है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक प्रदूषण की वजह से दिल्ली के लोगों की उम्र में दस साल की कमी आ रही है। बावजूद इसके कोई भी सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है।

क्या दिल्ली वाले अपने भविष्य के बारे में सोच पाएंगे?

दिल्ली के सामने प्रदूषण पानी की समस्या, यमुना की सफाई, कचड़े के पहाड़ों की बढ़ती समस्या जैसे कई मुद्दे हैं। दिल्ली की जनता इन गंभीर मुद्दों पर बात करने वाले दलों का इंतजार कर रही है। अब देखना है कि कौनसा दल दिल्लीवासियों की इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए वास्तविक और प्रभावी कदम उठाएगा। पर्यावरण और प्रदूषण की समस्या सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश की समस्या है।

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण की गंभीरता आज मानव अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। विश्व भर में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। 2023 में, भारत में अकेले बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं से 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि अगर वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ता है, तो दुनिया के लगभग 40% लोग जल संकट का सामना करेंगे। भारत, जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है, इस संकट के केंद्र में है। बावजूद इसके, राजनीतिक दल इन समस्याओं को गंभीरता से लेने के बजाय उन्हें दरकिनार करते नजर आते हैं। दिल्ली आज विश्व के सबसे प्रदूषित शहर में आती है। वायु गुणवत्ता लगभग पूरे साल ख़राब श्रेणी में रहती है। कचड़े का पहाड़ों की संख्या और ऊंचाई बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दलों की उदासीनता का आलम यह है कि चुनावी घोषणापत्रों में पर्यावरणीय मुद्दों का उल्लेख केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रमुख राजनीतिक दलों ने पर्यावरण से जुड़े कुछ वादे किए थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर केवल कागजों तक सीमित रह गए। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार ने 2019 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2024 तक हर घर में पानी पहुंचाने का वादा किया था। लेकिन 2023 तक, केवल 62% घरों को ही नल का जल उपलब्ध हो सका। इसी तरह, पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत ने 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसके लिए निवेश और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 2020 के चुनाव में दिल्ली की जनता से वायदा किया था कि अगर 2025 तक यमुना को स्वच्छ नहीं करेंगे तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन आज 2025 में भी यमुना नदी की स्थिति जस की तस है और अरविन्द केजरीवाल चुनाव भी लड़ रहे हैं।

विकास के लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण होना जरूरी

(पेज 5 से जारी)

बिना द्वेष से किया गया विकास ही सही मायने में लाभदायक होता है। छिंदवाड़ा से जो युवा विधायक और सांसद हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वह भविष्य की योजनाओं को देखकर समझ कर और दूर दृष्टिकोण के साथ अपने क्षेत्र का विकास करें, योजना बनाएं, अवसर तलाशें और तब युवाओं के भविष्य की रचना करें। जिससे आने वाला समय युवाओं के हाथ में शिक्षा एवं रोजगार के साथ बेहतर भविष्य भी दे।

मैंने बूंद-बूंद कर सिंचित कर छिंदवाड़ा जिले को अब एक नया स्वरूप देने की योजना पर कार्य किया है। छिंदवाड़ा को देश का मॉडल जिला बनाया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भाजपा शासन आते ही उस मॉडल को बर्बाद करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। पांच दशकों के अपने अथक प्रयास से जिस तरह से छिंदवाड़ा को विकसित करने का कार्य किया था वर्तमान भाजपा नेतृत्व और उसके नेता इस मॉडल को तहस-नहस करने में जुटे हुये हैं। अपनी सकारात्मक छवि बनाने के लिये मेरे द्वारा शुरू किये गये कार्यों को बंद करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं।

दलगत राजनीति से उठकर हो विकास

स्वतंत्रता के लगभग 75 वर्ष से अधिक के काल में मध्यप्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में आज भी पिछड़े राज्यों में शामिल है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहां की राजनीति और उससे जुड़े लोग। जब भी जिस पार्टी को भी प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने का अवसर मिला उसने सिर्फ अपने हितलाभ से जुड़े फैसले लिये और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मप्र भाजपा के पिछले दो दशक। प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल से लेकर अब तक जो भी योजनाएं बनी उनमें कहीं न कहीं केंद्र में राजनैतिक दल, राजनीति से जुड़े लोग या फिर प्रभावी समूह रहे हैं। यही कारण है कि आज भी मध्यप्रदेश विकसित राज्यों की सूची में नंबर वन नहीं बन पाया है। वहीं, इसी राज्य का एक जिला है छिंदवाड़ा। वर्षों तक विकास की योजना से कोसों दूर रहा। छिंदवाड़ा जिले का कायाकल्प लगभग चार दशक पहले आरंभ हुआ। मेरा उद्देश्य केवल राजनीति करना नहीं बल्कि समाजसेवा पहला धर्म है। समाजसेवा के पांच दशकों में जनता के दिलों पर अपनी एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जो आज तक लोगों के मन मस्तिष्क में बनी हुई है। इन वर्षों के दौरान, छिंदवाड़ा एक शांत और साधारण शहर से व्यापक सड़क और रेल नेटवर्क और एक मॉडल रेलवे स्टेशन के साथ उद्योगों के केंद्र में बदल गया।

OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला

(पेज 5 से जारी)

ओबीसी वर्ग के प्रति लिया गया सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला

यह मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के प्रति लिया गया सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला था। लेकिन बाद में मेरी सरकार को षडयंत्रपूर्वक गिरा दिया गया और मार्च 2020 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भाजपा सरकार ने ओबीसी के खिलाफ षड्यंत्र शुरू किया। हाई कोर्ट का आदेश सिर्फ कुछ पदों पर लागू होना था लेकिन भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश में सभी जगह यह आदेश लागू कर 27% आरक्षण की हत्या कर दी। 18 अगस्त 2020 को भाजपा सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में यह मत दिया कि 14% आरक्षण के साथ ही सभी सरकारी विभागों में भर्तियां की जाएं। यह ओबीसी वर्ग के साथ खुला षड्यंत्र था। लेकिन अब माननीय उच्च न्यायालय ने 28 जनवरी 2025 के अपने आदेश में 27% आरक्षण के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज होने के साथ ही प्रदेश में 27% आरक्षण लागू करवाने के दरवाजे खुल गए हैं।

वर्तमान राज्य सरकार की जिम्मेदारी है: कमलनाथ ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि तुरंत सभी भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने के प्रावधान किए जाएं। मैंने और कांग्रेस सरकार ने ओबीसी को जो 27 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार दिया था उसे सुनिश्चित करना वर्तमान राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

ओबीसी आरक्षण 27% करने के विरोध में दायर याचिकाएं

यूथ ऑफ इक्वैलिटी संगठन की तरफ से ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने के विरोध में दो याचिकाएं दायर की गयी थीं। जिसमें से एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती के लिए 87%-13% फार्मूला लागू करने के अनुमति दी थी। जिसके तहत 14 प्रतिशत आरक्षण के साथ 87 प्रतिशत पर सरकार नियुक्ति कर सकती थी। बचे हुए 13 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति होल्ड रखी गयी थी। याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने पाया कि याचिका में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने के सर्कुलर को चुनौती दी गयी थी, एक्ट को नहीं। जिसके कारण उस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया गया।

27 प्रतिशत आरक्षण के साथ हो सभी परिक्षाएं: उमंग सिंघार

अब बिना देरी के सभी भर्ती परीक्षाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, ताकि छात्रों को उनका हक मिले। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 87:13 के फॉर्मूले को खारिज कर दिया है। जिससे अब ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने भाजपा सरकार के 87%-13% फॉर्मूले को खारिज कर दिया, जो ओबीसी को 27% आरक्षण से वंचित करने की साजिश थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 69 याचिकाएं लगाकर भी अड़ंगा डालने की कोशिश की थी।

क्या भूपेश बघेल के लाडले अशोक जुनेजा को भाजपा देगी सेवा विस्तार?

तीन बार सेवा विस्तार पा चुके भ्रष्टाचारी जुनेजा के हाथ सेवानिवृत्ति आएगी या फिर मिलेगा अभयदान?

(पेज 1 से जारी)

क्या यही कारण है कि गृहमंत्री एक बार फिर प्रदेश के सबसे अधिक भ्रष्टाचार में लिप्त रहे पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा को सेवा विस्तार देने की योजना पर काम कर रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप घोटाले से लेकर शराब घोटाला, कोयला घोटाला सहित बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने आदि को अंजाम देने वालों की दाल बनने वाले अशोक जुनेजा को लगातार तीसरी बार सेवा विस्तार देने का फैसला राज्य की जनता के चेहरे पर अपंग कानून का करारा थप्पड़ साबित होगा। सरकार ने जुनेजा को सेवा विस्तार दिया तो यह दिन राज्य के लिए काला दिन साबित होगा, खासतौर पर जब छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था अब हाथ से निकल गई है। बघेल सरकार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अशोक जुनेजा को इस समय गृह विभाग से भरपूर सहयोग मिल रहा है। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि जुनेजा ने गृहमंत्री और उनके सहयोगियों को बड़े स्तर पर उपकृत कर दिया है , जिसके एवज में अब जुनेजा को सेवा विस्तार देने की योजना बना रहे हैं।

बघेल के मुख्य सेनापति रह चुके हैं जुनेजा

अशोक जुनेजा के बारे में यह भी कहा जाता रहा है कि वह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार में पावरफुल अफसरों में सौम्या चौरसिया के बाद आते थे। उनकी बघेल सरकार में तूती बोलती थी। यही कारण है कि भूपेश बघेल ने अशोक जुनेजा को अपने भ्रष्टाचार तंत्र का एक मोहरा बनाया और उन्हें भ्रष्टाचार करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया। जुनेजा ने भी अफसरशाही की चिंता किए बगैर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। इसी तरह जुनेजा मुख्यमंत्री बघेल के करीबी अफसरों में शामिल हो गए।

अब भाजपा नेता क्यों नहीं लेते एक्शन?

जुनेजा और भाजपा के गृहमंत्री के बीच पनप रही दोस्ती के चर्चे इस बात को लेकर भी आम है क्योंकि जिस समय बघेल सरकार में जुनेजा भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे थे उस समय यही भाजपा नेता उनका विरोध करते। लेकिन आज जब स्वयं सत्ता में हैं तो जुनेजा के टुकड़ों के आगे नतमस्तक हो गए और उनके खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं करना उचित समझा। जनता का सेवक होकर जनता के विश्वास से खिलवाड़ करने का यह दंड आने वाले समय में विष्णुदेव साय सरकार को भी मिल सकता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इस अवस्था में भी मुख्यमंत्री साय सेवा विस्तार पर विचार करेंगे।

04 फरवरी को होना है रिटायरमेंट

जानकारी के अनुसार अशोक जुनेजा पहली बार वर्ष 2021 में भूपेश बघेल सरकार में पुलिस महानिदेशक बने। उसके बाद वर्ष 2023 में उन्हें रिटायरमेंट देने के बजाय बघेल सरकार ने उन्हें सेवा विस्तार दिया और उनकी रिटायरमेंट तिथि 04 फरवरी 2025 हो गई। अब देखने वाली बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर सहित ब्यूरोक्रेसी को कठघरे में खड़ा कर देने वाले जुनेजा को 04 फरवरी को क्या मिलेगा। सेवानिवृत्ति या सेवा विस्तार।

बड़ा लेन देन की है खबर

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बहुत मोटी रकम का लेन-देन किया है, यह जांच का विषय है? पूर्व में हुए आरटीओ और अवैध पुलिस थानों की उगाही के मामले में भी सरकार को जांच करनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ को सुशासित, विकसित और खुशहाल बनाने के संकल्प के साथ प्रगति पथ आगे बढ़ रहे मुख्यमंत्री साय

(पेज 1 से जारी)

परिषद के गठन का फैसला किया

छत्तीसगढ़ में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई औद्योगिक नीति को लागू किया है। 1 नवंबर से नई औद्योगिक नीति लागू हो गई है। नई औद्योगिक नीति में पर्यटन पर भी फोकस किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का फैसला किया गया है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में गरीब लोगों के घर के निर्माण पर फैसला किया गया। राज्य में पीएम आवास योजना के दूसरे चरण का सर्वे चल रहा है। केंद्र सरकार ने 846313 नए आवासों को स्वीकृति दी। राज्य में 1 लाख 74 हजार 585 लोगों को नए आवास सौंपे जा चुके हैं। वहीं, हाउसिंग बोर्ड के तहत 50 हजार घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

युवाओं को साधने के लिए सरकार

विष्णुदेव साय की सरकार ने युवाओं पर भी फोकस किया है। युवाओं को साधने के लिए सरकार ने होनहार छात्रों को ब्याजमुक्त कर्ज देने की घोषणा की है। नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के कई निकायों में हाइटेक लाइब्रेरी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार होने से छत्तीसगढ़ को कई फायदे मिले हैं। बीते एक साल में प्रदेश में 31 हजार करोड़ रुपये के सड़क और राजमार्ग के कामों को स्वीकृति दी गई है। राज्य के चार प्रमुख शहरों में ई-बसों की शुरुआत का फैसला लिया गया है। अंबिकापुर में हवाई सेवा की शुरुआत की गई है।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

राज्य में बीजेपी ने घोषणा की थी सरकार बनने के बाद श्रद्धालुओं के लिए रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के श्रद्धालुओं को फ्री में अयोध्या का दर्शन कराया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की एक बार फिर से शुरुआत की गई है। सरकार ने हेल्थ के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है। हाल ही में बिलासपुर में 200 करोड़ रुपये का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया गया है। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल की नई बिल्डिंग के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। सरकार के इस फैसले पर पूर्व डेप्युटी सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता टीएस सिंहदेव भी तारीफ कर चुके हैं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)